कर्नाटक राज्य

बनाम

भास्कर कुशाली कोठारकर और अन्य

19 अगस्त, 2004

[के.जी. बालकृष्णन और डॉ. ए.आर. लक्ष्मणन, जे.जे.]

आपराधिक मुकदमा:

जांच अधिकारी की गैर-परीक्षा-आरोपियों पर अन्य बातों के साथ-साथ अभियोजन का प्रभाव- 304 (भाग II) आर/डब्ल्यू. एस. 149 आईपीसी- ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि-एफआईआर दर्ज करने वाले जांच अधिकारी और हेड कांस्टेबल की जांच न करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा बरी करना- माना गया, निष्पक्ष सुनवाई के एक भाग के रूप में जांच अधिकारी से जांच की जानी चाहिए-तथ्यों पर, क्योंकि आरोपी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं थे आई.ओ. की जांच न होना और कांस्टेबल जिसने एफआईआर दर्ज की थी, उच्च न्यायालय द्वारा केवल तकनीकी आधार पर दोषसिद्धि को पलटना उचित नहीं था- यह साबित करने के लिए बहुत मजबूत और ठोस सबूत हैं कि आरोपी ने अपराध किया- ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि के रिकॉर्ड को बहाल किया गया- साक्ष्य- की सराहना।

बिहारी प्रसाद और अन्य बनाम बिहार राज्य, [1996] 2 एससीसी

317 और बहादुर नाइक बनाम बिहार राज्य, [2000] 9 एससीसी 153, पर भरोसा किया गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 498/ 1998

कर्नाटक उच्च न्यायालय के सीआरएल ए. क्रमांक 82/1995 में निर्णय और आदेश दिनांक 06-08-1996 से।

अपीलकर्ता की ओर से अनिल के. मिश्रा और संजय आर. हेगड़े।

आर.एस. हेगड़े, चंद्र प्रकाश, सुश्री सावित्री पांडे और पी.पी. सिंह प्रतिवादियों के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश सुनाया गया-

कर्नाटक राज्य ने आईपीसी की धारा 149 और आईपीसी की धारा 324/148 और आईपीसी की धारा 143 के साथ पठित धारा 304 भाग II के तहत दंडनीय अपराध के लिए 1 से 4 तक उत्तरदाताओं को बरी करने को चुनौती देते हुए यह आपराधिक अपील दायर की है। सत्र न्यायालय, कारवार द्वारा 1 से 4 तक उत्तरदाताओं को दोषी पाया गया और इससे व्यथित होकर उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील दायर की और अपील की अनुमति दी गई।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि प्रतिवादी 4 से 4 तक तीन अन्य लोगों के साथ शाम लगभग 7.30 बजे मृतक प्रकाश मंजूनाथ

तालेकर के आवास पर गए। 20.9.1993 को. ये उत्तरदाता और अन्य लोग साइकिल चेन, बेल्ट और डंडों से लैस थे। मृतक प्रकाश को पहले प्रतिवादी और दूसरे प्रतिवादी ने उसके घर से 75 फीट की दूरी तक घसीटा, जहां उस पर आरोपियों ने बेल्ट, साइकिल चेन और डंडों से हमला किया। पीडब्लू-1, मृतक प्रकाश की पत्नी शोभा अपने पति के बचाव में आई और आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। पीडब्लू-2 ताराबाई जो घटना के समय मृतक के घर में मौजूद थी, उसके साथ भी आरोपी ने मारपीट की। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि पीडब्लू-10 सीताबाई जो किसी समारोह में भाग लेने के बाद आ रही थीं, उनके घर जाते समय इन आरोपियों ने उन पर हमला किया। घटना के करीब 10 मिनट बाद प्रकाश की मौत हो गयी। पीडब्लू-1 पुलिस स्टेशन जाने से डर रही थी और अगले दिन सुबह वह पास के पुलिस स्टेशन गई और एफआई बयान दिया। उसका बयान दर्ज किया गया और मामला दर्ज किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पीडब्लू-1 से पीडब्लू-11 तक का परीक्षण किया गया। मृतक प्रकाश का पोस्टमार्टम पीडब्लू-11 द्वारा किया गया। उनके शरीर पर लगभग 22 चोटें थीं और अधिकांश चोटें खरोंच की थीं और आंतरिक चोटों से पता चलता है कि 7 वीं, 8 वीं जगह पर फ्रैक्चर थे। बायीं ओर 9 वीं और 10 वीं पसलियाँ। पूरी बायीं किडनी के आसपास खून के थक्के थे। पोस्टमार्टम करने वाले पीडब्लू-11 ने बताया कि सभी चोटें पोस्टमार्टम से पहले की थीं और घायल की मौत कई चोटों के कारण सदमे

और रक्तस्राव के कारण हुई।

सत्र अदालत ने पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-10 के साक्ष्यों पर भरोसा किया और प्रतिवादियों 1 से 4 तक को दोषी ठहराया। उनके द्वारा दायर अपील में, उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने केवल इस आधार पर दोषसिद्धि और सजा को पलट दिया कि एफआई बयान दर्ज करने वाले जांच अधिकारी और कांस्टेबल से अभियोजन गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई थी। जहां तक चश्मदीद गवाहों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का संबंध है, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी पारित नहीं की गई।

राज्य के वकील ने कहा कि आरोपी को बरी करना कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है क्योंकि जांच अधिकारी और एफआई बयान दर्ज करने वाले कांस्टेबल से पूछताछ न किए जाने के कारण आरोपी को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ।

मौजूदा मामले में, सत्र न्यायाधीश ने इन दोनों गवाहों को समन जारी किया लेकिन ये पुलिस अधिकारी साक्ष्य देने के लिए उपस्थित नहीं हुए और सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन मामले को बंद कर दिया क्योंकि एक आरोपी काफी लंबे समय से विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में था। प्रथम से 4 तक के उत्तरदाताओं के वकील ने हालांकि तर्क दिया कि जांच अधिकारी की गैर-परीक्षा से वे गंभीर रूप से पूर्वाग्रहग्रस्त थे, लेकिन इस दलील को ठोस तथ्यों और परिस्थितियों से प्रमाणित नहीं किया जा सका।

यह सच है कि निष्पक्ष सुनवाई के एक हिस्से के रूप में जांच अधिकारी से मुकदमे के मामलों में पूछताछ की जानी चाहिए, खासकर जब आरोपी के खिलाफ गंभीर सत्र मुकदमा चल रहा हो। यदि अभियोजन पक्ष का कोई भी गवाह धारा 161 Cr के तहत दर्ज किए गए अपने पिछले बयान के विपरीत कोई सबूत देता है। पी.सी. या यदि कुछ महत्वपूर्ण विवरणों में कोई चूक है, तो इन गवाहों के पिछले बयान को केवल उस जांच अधिकारी की जांच करके साबित किया जा सकता है जिसने धारा 161 सीआर के तहत इन गवाहों के बयान दर्ज किए होंगे। पी.सी. वर्तमान मामले में, महत्वपूर्ण चश्मदीद गवाह पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-10 के साक्ष्य के संबंध में ऐसा कोई गंभीर विरोधाभास इंगित नहीं किया गया है। इसलिए एफआई का बयान दर्ज करने वाले हेड कांस्टेबल से पूछताछ न करना भी गंभीर परिणाम नहीं है क्योंकि पीडब्लू-1 की जांच इस तथ्य को साबित करने के लिए की गई थी कि उसने पुलिस के सामने बयान दिया था। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह कहकर सत्र न्यायालय के आदेश को पलटना उचित नहीं था कि जांच अधिकारी और एफआई बयान दर्ज करने वाले कांस्टेबल की गैर-परीक्षा के कारण आरोपी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दो चश्मदीद गवाहों और पीडब्लू-10 के साक्ष्य पर विस्तार से विचार नहीं किया। तकनीकी आधार पर अपील का निस्तारण कर दिया गया। पीडब्लू-1 कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी है। पीडब्लू-2 एक पड़ोसी है जो कुछ किराने का सामान खरीदने के लिए घटना स्थल पर

आया था। पीडब्लू-1 ने बताया कि उत्तरदाता 1 से 4 और अन्य लगभग 7/7.30 बजे उसके घर आए। 20.9.1993 को, पहले आरोपी भास्कर कुशली कोठारकर और 5 वें आरोपी दत्तरन कुशली कोठेरकर ने उनके पति को घसीटा और उसके बाद सभी आरोपियों ने उनके शरीर पर कई चोटें पहुंचाईं। उसने इन उत्तरदाताओं की पहचान की और हमें उसके साक्ष्य में कोई कमज़ोरी नहीं मिली।

प्रतिवादियों के वकील ने बताया कि पुलिस को एफआई बयान देने में काफी देरी हुई। पीडब्लू-1 ने कहा कि वह पुलिस स्टेशन जाने से डरती थी और वह अगले दिन ही गई। उत्तरदाताओं के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि पीडब्लू-1 के सास-ससुर और कई अन्य रिश्तेदार पास के घरों में रह रहे थे और वह उनमें से किसी एक की सहायता मांग सकती थी और चूंकि उसने ऐसा नहीं किया था, इसलिए उसका साक्ष्य संदेहास्पद है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें नहीं लगता कि इस गवाह के साक्ष्य को इस आधार पर खारिज किया जा सकता है, खासकर तब जब उसका साक्ष्य पीडब्लू-2 के साक्ष्य से पुष्ट हो। पीडब्लू-2 ने यह भी बताया कि ये सभी उत्तरदाता और अन्य लोग घटना स्थल पर आए और मृतक प्रकाश, उस पर और पीडब्लू-1 पर हमला किया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीडब्लू-2 को सात से अधिक चोटें आईं और ये चोटें घटना के समय हमलावरों के हाथों लगी होंगी। पीडब्लू-1 को दाहिनी जांघ और पैर के दाहिनी ओर चोटें आईं।

पीडब्लू-10 एक अन्य महत्वपूर्ण गवाह है जिसे प्रतिवादियों और अन्य आरोपियों द्वारा उस समय चोटें लगी थीं जब वे घटना स्थल से वापस जा रहे थे। पी डब्ल्यू-10 मृतक प्रकाश की मां हैं। वह गणेश उत्सव में शामिल होने गई थी और रात करीब 8 बजे जब वह अपने घर लौट रही थी तो सभी सात आरोपी आए और आरोपी नंबर सात ने उस पर साइकिल की चेन से हमला कर दिया। उसे गंभीर चोटें आईं और उसके दो दांत टूट गए।

यह साबित करने के लिए बहुत मजबूत और ठोस सबूत हैं कि इन उत्तरदाताओं ने अन्य लोगों के साथ मिलकर मृतक प्रकाश, पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 पर हमला किया था। सत्र न्यायाधीश ने इन उत्तरदाताओं को दोषी ठहराने के लिए वैध कारण बताए थे। एकल न्यायाधीश द्वारा केवल इस आधार पर दोषसिद्धि और सजा को पलटना उचित नहीं था कि अभियोजन पक्ष द्वारा जांच अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई थी। चूंकि उत्तरदाताओं को जांच अधिकारी और एफआई बयान दर्ज करने वाले कांस्टेबल की गैर-परीक्षा से कोई पूर्वाग्रह नहीं था। विद्वान एकल न्यायाधीश का निष्कर्ष गलत है, इसलिए, हम उसे रद्द करते हैं।

बिहारी प्रसाद और अन्य बनाम बिहार राज्य, [1996] 2 एससीसी 317 में, इस न्यायालय ने माना कि जांच अधिकारी की गैर-परीक्षा अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं है, खासकर जब आरोपी को कोई

पूर्वाग्रह झेलने की संभावना नहीं थी। बहादुर नाइक बनाम बिहार राज्य, [2000] 9 एससीसी 153 में, इस न्यायालय ने माना कि जब कोई भौतिक विरोधाभास सामने नहीं लाया गया है, तो अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में जांच अधिकारी की गैर-परीक्षा का कोई परिणाम नहीं होगा और ऐसी परिस्थिति में ऐसी गैर-परीक्षा से अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

परिणामस्वरूप, हम राज्य द्वारा की गई अपील को स्वीकार करते हैं और सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई सजा के फैसले को बहाल करते हैं। वर्ष 1996 में उच्च न्यायालय के फैसले से उत्तरदाताओं को बरी कर दिया गया और घटना 1993 में हुई। मामले के इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सात साल की कारावास की सजा को घटाकर पांच साल कर दिया गया है। 1 से 4 उत्तरदाताओं को सजा की शेष अवधि काटने के लिए अपने जमानत बांड में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुमन मुंडोटिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।